DAINIK JAGRAN: 1 सितम्बर, 2018

1. 2021 में आम जनगणना के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आंकड़े अलग से जुटाए जाएंगे

- मंडल कमीशन के आधार पर **ओबीसी को 27 फीसद का आरक्षण** दे दिया गया, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट **1931 की जनगणना के आंकड़ों पर** आधारित थी। वहीं 2006 में ओबीसी की जनसंख्या का अंदाजा लगाने के लिए एनएसएसओ सर्वे किया गया था, जिसके अनुसार देश में कुल जनसंख्या का 41 फीसद ओबीसी है।
- सरकार पिछड़ी जातियों को देश के विकास में भागीदार बनाने के प्रति गंभीर है। सरकार इस प्रतिबद्धता का परिचय पिछले महीने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर भी दे चुकी है।
- जनगणना में अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेने का निर्देश, ताकि आंकड़े तीन साल के भीतर जारी किए जा सकें। जनगणना के त्वरित आंकड़ों के लिए 25 लाख लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने में आठ साल तक का वक्त लग जाता था।

2.बिम्सटेक के मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को परोक्ष तौर पर नसीहत,

- इसमें कहा गया है कि किसी भी देश को किसी भी तरह के **आतंकवाद का ना तो समर्थन करना चाहिए** और ना ही **सीमा पार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा** देना चाहिए।
- दक्षिण एशिया में पाकिस्तान व मालदीव को छोड़कर अन्य सभी देश (भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाइलैंड व म्यांमार) इसके सदस्य,
- बे ऑफ **बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकोनामिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) की स्थापना वर्ष 1997** में

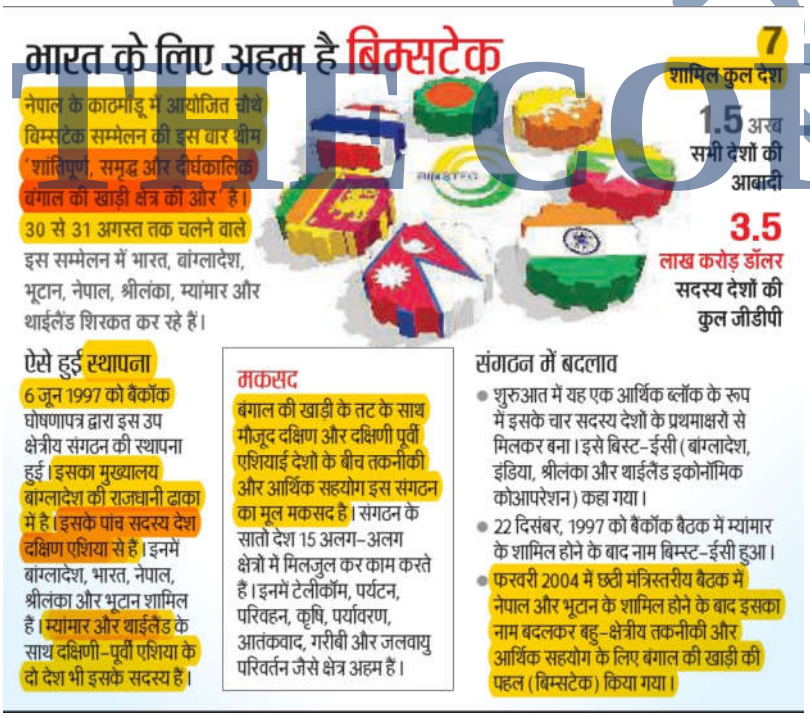

- इस संगठन के अधिकांश देश बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं और इस समुद्री क्षेत्र की अहमियत अमेरिका की हिंद-प्रशांत महासागर में बढ़ रही दिलचस्पी की वजह से बढ़ गई है। भारत भी चाहता है कि सार्क की जगह यह संगठन ही तेजी से आगे बढ़े।
- इनमें यह सहमति भी बनी है कि **हर देश अपने स्तर पर इसे क्षेत्रीय व अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी खास तवज्जो दिलाएंगे।**
- सदस्य देशों के मध्य साझा ट्रांसपोर्ट व संचार व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी देशों के बीच राजमार्गो, रेलवे नेटवर्को, समुद्री मार्गो का साझा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2025 का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह मास्टर प्लान चीन की कनेक्टिविटी परियोजना (बीआरआइ) का जवाब होगा।
- बिम्सटेक देशों ने मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी सहमति बनाने का निर्णय लिया |

3.गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना 'आयुष्मान भारत'

- केंद्र सरकार 25 सितंबर को इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से शुरू करेगी।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में कराई गई सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर स्वास्थ्य बीमा देने का दिशानिर्देश,

©TheCoreIAS

- दिल्ली सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं |

4.मौसम विभाग के मानसून पूर्व किए गए पूर्वानुमान से परे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इस बार 23 फीसद तक कम बारिश हुई

- इसके पीछे एक वजह तो यह है कि यहां तक आते-आते मानसून टर्फ के साथ हवा भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है।
- साथ-ही राज्यों में बढ़ रही निर्माण गतिविधियां, घटती हरियाली और किसी प्रमुख नदी-नहर का नहीं होना भी इसकी वजह है।

5.ऑस्ट्रेलिया में 25 देशों के साथ अभ्यास करेगी भारतीय नौसेना

Use: (Paper II: International Relation)

- दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में चार महीने तक तैनात रहने के बाद भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत आइएनएस सह्याद्री आस्ट्रेलिया के नौसैनिक बंदरगाह डार्विन पहुंच गया है। यहां वह बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2018 में भाग लेगा |
- 1993 से शुरू ककाडू अभ्यास रॉयल आस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित और रॉयल आस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास हर दो साल पर डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्रों (एनएएक्सए) में आयोजित होता है।

6.समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं: विधि आयोग

- विवाह, तलाक, गुजारा खर्च और पुरुष एवं महिलाओं की शादी की उम्र से संबंधित कानून में बदलाव का सुझाव,
- धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में इसके मजबूत संरक्षण की बात करते हुए आयोग ने कहा है कि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तीन तलाक और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को धार्मिक परंपरा की आड़ लेकर अमल में लाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए,
- एक बार में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत पर विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अभी तक लंबित,
- आयोग ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विविधता विख्यात है, लेकिन खास समूह या समाज के कमजोर तबके को प्रक्रिया में वंचित नहीं रखा जा सकता |

THE CORE IAS

7.कचरा प्रबंधन नीति बनाने तक कुछ राज्यों में निर्माण पर रोक

- ठोस कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) पर उदासीन रवैये और उचित नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।

8.अनुच्छेद 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक सुनवाई टाली

- अनुच्छेद 35 ए : राष्ट्रपति के आदेश से **सन 1954** में शामिल किया गया |
- अनुच्छेद 35 ए **जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं** प्रदान करता है।
- यह अनुच्छेद ही शेष भारत के लोगों को जम्मू-कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से रोकता है।
- अगर कोई कश्मीरी महिला अन्य प्रदेश या देश के पुरुष से शादी करती है तो भी अचल संपत्ति पति के नाम स्थानांतरित नहीं हो सकती है। इस अनुच्छेद के कारण प्रदेश की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का गैर मूलवासियों का दावा खत्म हो जाता है।

9.चुनाव में नक्सलगढ़ पर आसमान से होगी निगहबानी (Pg 4)

- संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर व ड्रोन का होगा प्रयोग,

10. सरकार द्वारा खरीद में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस (GEM) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने कि योजना

- जीईएम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्यों में खरीदारों और विक्रेताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- साथ ही इस अवधि में खरीदारों और विक्रेताओं का पंजीकरण भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर कराने पर जोर होगा।
- फ़िलहाल सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके जरिये खरीदारी कर रहे हैं।

11.रोजगार के मोर्चे पर मिले अच्छे संकेत

अर्थव्यवस्था की ताजा तस्वीर		
क्षेत्र	2017-18	2018-19
कृषि, वानिकी मत्स्य	3.0	5.3
खनन	1.7	0.1
मैन्यूफैक्चरिंग	-1.8	13.5
बिजली, गैस, जलापूर्ति व अन्य सेवाएं	7.1	7.3
कंस्ट्रक्शन	1.8	8.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार सेवाएं	8.4	6.7
वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं	8.4	6.5
लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं	13.5	9.9

- आर्थिक विकास दर के जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2018) के दौरान मैन्यूफैक्चरिंग में 13.5 फीसद और कंस्ट्रक्शन उद्योग में 8.7 फीसद की वृद्धि दर हासिल हुई |
- आठ प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली क्षेत्र
- 6.6 फीसद की विकास दर हासिल की है।

12.रिकॉर्ड पैदावार ने कृषि क्षेत्र की बढ़ाई गति

- किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी प्रयास,बजट में कृषि क्षेत्र के लिए दोगुने आवंटन और नीतिगत फैसले लेने के साथ अमल पर जोर से और मानसून बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र ने शानदार 5.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, मोटे अनाज की वृद्धि दर 15.6 व दलहन की 17.3 फीसदी वृद्धि रही |

13.किसानों में डिजिटल जागरूकता फैलाने को गूगल से मांगी मदद

- किसानों के बीच मौसमी और वैज्ञानिक खेती के संबंध में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए,
- साथ ही डिजिटल विलेज सहित डिजिटल समावेशी कार्यक्रमों में गूगल से अधिक सहभागिता करने को कहा गया।

THE CORE IAS

14.सिंधु घाटी का दौरा करेंगे भारत-पाक के अधिकारी

15.एच-1बी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं कर रहा अमेरिका

16.केमिकल नदी

- शिमला से सोलन की ओर बहने वाली अश्विनी खड्ड के प्लास्टिक नदी के नामकरण के बाद अब बद्दी से सतलुज की तरफ बहने वाली सरसा व बाल्द नदी को केमिकल नदी का नाम दिया जा रहा है।
- दोनों ही नदियों में भारी प्रदूषण है और जीव-जंतुओं सहित मनुष्य जीवन के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं।

16.भूकंप के बाद के झटकों का पूर्वानुमान लगाएगा गूगल का नया एआइ सिस्टम |

18. कश्मीर में आतंकियों को स्टील बुलेट मुहैया करा रहा चीन

- फॉरेंसिक जांच में स्टील बुलेट के चीन में निर्मित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल इन स्टील बुलेट का इस्तेमाल सिर्फ जैश ए मोहम्मद के आतंकी आत्मघाती हमले के दौरान ही कर रहे हैं। हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने अभी स्टील बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। गौरतलब है कि आतंकियों के स्टील बुलेट जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सफल होते हैं।
- फॉरेंसिक जांच में स्टील बुलेट के चीन में निर्मित होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल इन स्टील बुलेट का इस्तेमाल सिर्फ जैश ए मोहम्मद के आतंकी आत्मघाती हमले के दौरान ही कर रहे हैं। हिजबुल

मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने अभी स्टील बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। गौरतलब है कि आतंकियों के स्टील बुलेट जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सफल होते हैं।

19.Malnutrition:

20. ट्रंप ने दी डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की धमकी

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर निकलने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि संगठन की संरचना में सुधार किया जाए अन्यथा अमेरिका उसे छोड़ देगा। कई वैश्विक संस्थाओं और समझौतों से बाहर निकलने के बाद यह ट्रंप की ओर से आई ताजा धमकी है

21.Editorials

1. विकास की नई धुरी बनता बिम्सटेक

What is BIMSTECH

- एक क्षेत्रीय समूह के रूप में बिम्सटेक दक्षिण एशिया के पांच (बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका) और दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देशों (म्यांमार और थाईलैंड) का सहयोग संगठन है।

Growing Stature of BIIMSTECH

- इस क्षेत्र का आर्थिक और सामरिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

THE CORE IAS

- 2016 में गोवा में आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के साथ हुए बिम्सटेक आउटरीच में सदस्य राष्ट्रों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति ने बिम्सटेक में जान फूंकने का काम किया।
- विगत दो वर्षो में बिम्सटेक की कई उपलब्धियों को देखा जा सकता है।
- मसलन बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक, आपदा प्रबंधन अभ्यास, टूर ऑपरेटरों की बैठक, पारंपरिक दवा के क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन, बिम्सटेक टेली-मेडिसिन नेटवर्क की स्थापना, व्यापार और औद्योगिक समूहों की बैठकें।
- **Connectivity:** एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बिम्सटेक देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान लगभग तैयार कर लिया है।
- सदस्य देशों के बीच तटीय शिपिंग समझौते और मोटर वाहन समझौते पर सकारात्मक बातचीत की जा रही है। बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना पर एमओयू के लिए भी बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग पर सदस्य देशों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गैर-पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग में काफी प्रगति हुई है।
- कुल मिलाकर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, परिवहन और संपर्क, पर्यटन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, ऊर्जा एवं लोगों के आपसी संपर्क सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

BIMSTECH & Its Importance

- बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।
- संपर्क, व्यापार एवं निवेश और सांस्कृतिक संबंधों के विभिन्न आयामों के विस्तार के लिए सुझाए गए कदमों के कार्यान्वयन से समूह में एक प्रभावी एशियाई संस्थागत सहयोग विकसित करने की विशाल क्षमता है।
- दरअसल इंडो-पैसिफिक यानी हंिदू-प्रशांत क्षेत्र की धारणा के पुनर्जन्म के साथ ही बंगाल की खाड़ी का आर्थिक और सामरिक महत्व और भी तेजी से बढ़ रहा है।
- यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि बंगाल की खाड़ी और उसके तटवर्ती राष्ट्र Hind- प्रशांत क्षेत्र में विकास के नैसर्गिक केंद्रबिंदु के रूप में उभर रहे हैं।
- बंगाल की खाड़ी एक समय वैश्विक इतिहास के केंद्र में थी, जो बदलते राजनीतिक परिवेश में अप्रासंगिक हो गई। इस क्षेत्र की समृद्ध आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून, 1997 को बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्सटेक सहयोग की पहल हुई।
- यद्यपि बिम्सटेक प्रक्रिया अपने अस्तित्व के तीसरे दशक में प्रवेश कर गई है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने में पिछले दो दशक में अभी तक उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, लेकिन दो वर्षो में सदस्य देशों के बीच नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है।

Leadership of India must to revive BIMSTECH

भारत के पड़ोस में कुछ शक्तियों की अनौपचारिक और अक्सर टकराव की स्थिति के कारण कई देशों की ओर से बिम्सटेक को प्राथमिकता दी जा रही है। इस संगठन की दशा और दिशा तय करने में भारतीय नेतृत्व न केवल अहम, बल्कि अनिवार्य है। भारत सरकार ने बिम्सटेक सदस्यों के साथ बहुआयामी सहयोग के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और धीरे-धीरे प्रगति भी हो रही है, किंतु भारत से अपेक्षित है कि वह बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में और ध्यान दे। उसे इस संगठन को दक्षेस के विकल्प के रूप में खड़ा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बिम्सटेक के तहत तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधारों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और अधिक प्रतिबद्धता की जो अपेक्षा है उस पर भारत को खरा उतरना चाहिए। बेहतर हो कि भारत बिम्सटेक सचिवालय को मजबूती प्रदान

THE CORE IAS

करने के लिए अपने स्तर पर ठोस कदम उठाए ताकि सदस्य देशों को सहमति वाले मुद्दों के क्रियान्वयन में संस्थागत सहयोग मिले। बंगाल की खाड़ी को सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए शीर्ष नेताओं के बीच संवाद की आवृति बढ़ने और वादों के निस्तारण से बिम्सटेक निश्चित रूप से HIND -प्रशांत क्षेत्र में विकास की धुरी बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रलय के वक्तव्य में ठीक ही कहा गया कि बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी में हिमालय की अनूठी पारिस्थितिकी को जोड़ता है। साझा विरासत, साझा मूल्यों और जीवन के साझा तरीकों के साथ बिम्सटेक HIND -प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्वाभाविक मंच है। बिम्सटेक सदस्यों के बीच सहयोग में प्रगति, भारत के पूवरेत्तर राज्यों के विकास और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को गति भी प्रदान करेगा

2. लोकतंत्र और वैचारिक असहमति

Importance of Right to speech for democracy

- विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा तत्व है जो आम लोगों को स्वयं संप्रभु होने का एहसास प्रदान करता है।
- विचारधारा सामान्य नागरिक का, समाज का एवं विभिन्न संगठनों आदि का बौद्धिक प्राण तत्व है।
- विचार एवं विचारधारा ही व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि व्यवहार व निर्णयों को आधार प्रदान करता है।
- लोकतंत्र स्वयं एक विचारधारा है जो मूल्य एवं संस्थाओं का रूप धारण कर व्यक्तियों को लोकतांत्रिक जीवनशैली एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण का विचार प्रदान करती है।
- जब बात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की होती है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वयं ही निहित होती है। चाहे अब वह विचार सहमति की हो अथवा असहमति की, दोनों ही समान रूप से लोकतंत्र में पवित्र है।

THE CORE IAS

Other side of story

- सत्य तो यह है कि लोकतंत्र को स्वस्थ्य रखने के लिए असहमति के विचार को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि असहमति की स्वीकार्यता ही लोकतंत्र का प्राण है। अत: असहमति के सेफ्टी वॉल्व की अवधरणा सर्वाधिकारवादी शासन के लिए उचित कथन हो सकता है, परंतु भारत जैसे लोकतंत्र के लिए नहीं। कुछ विचार एवं विचारधारा समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं कल्याण करने की परिधि को तोड़कर राष्ट्र के विनाश के लिए भी प्रयासरत रहती है।
- ऐसी विचारधारा को सहमति अथवा असहमति की परिधि से बाहर लाकर देखने की जरूरत होती है। लोकतंत्र की यह कैसी असहमति है जो देश की लोकतांत्रिक संस्था के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की हत्या के षडयंत्र रचने तक की स्वतंत्रता पाना चाहती है।
- हमारा लोकतंत्र किस दिशा में बढ़ चला है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वालों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता की दुहाई देकर बचाने का मुहिम चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नक्सली एवं षडयंत्र में शामिल ही हैं, परंतु पुलिस ने यदि इन्हें पकड़ा है तो कुछ तो आधार तत्व होगा।
- कोई भी आंदोलन बिना विचारधारा के जीवित नहीं रह सकता है, तो क्या झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि के जंगलों में कंधों पर हथियार लटकाए अशिक्षित युवा इस नक्सली विचारधारा की रचना करते हैं। नहीं, इन विचारधाराओं की रचना दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों एवं विदेशों में बैठे अतिबौद्धिक लोग करते हैं। इन बौद्धिकों के कलम की स्याही देश के सुदूर जंगलों, छोटे शहरों, कस्बों में छुपे बैठे नक्सली कॉमरेडों तक गोली, बमों, बारूदों द्वारा सिस्टम के लोगों का खून बहाने का रूप धारण कर लेती है। यह कैसी असहमति है जो पिछले करीब 50 वर्षों से देश में हजारों लोगों की जान ले चुकी है। भारतीय लोकतंत्र तो इतना सहज है कि किसी को जातिवाद की विचारधारा फैलाकर तो किसी को लोकलुभावन नारों द्वारा बेहद कम समय व कम संघर्ष से भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा देता है।

अर्थात भारतीय लोकतंत्र में सभी के लिए अवसर है, तो फिर नक्सली आंदोलन क्यों? और यदि देश में नक्सली आंदोलन हुआ भी तो अब तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? सवाल यह है कि आज भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जीवन की चिंता के बजाए उनके विरुद्ध साजिश करने वाली ताकतों की रक्षा की चिंता समस्त विपक्ष कर रहा है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तार लोग दोषी ही हैं परंतु जिस मामले में वे शक के दायरे में आए हैं उसकी गंभीरता की चिंता किसी को नहीं है।

- यदि वे बेकसूर हैं तो कानून उन्हें अवश्य छोड़ देगा। परंतु यदि वे दोषी साबित होंगे तो उनका साथ देने वाले तमाम लोग एवं संस्था भारत के लोकतंत्र एवं लोगों को क्या उत्तर देंगे।

(Not to take these points)

- नक्सली आंदोलन की उम्र देखकर यह सहज अंदाजा होता है कि इस आंदोलन का समाधान से ज्यादा इसका बना रहना कांग्रेस नेतृत्व के लिए लाभकारी रहा है और आज ऐसे लोगों के पक्ष में शीर्ष कांग्रेसी नेता वकीलों की सर्वोच्च न्यायालय में उतरी फौज स्वयं ही तस्वीर को स्पष्ट कर रही है। इसी देश में फर्जी मामलों में, छोटे-मोटे अपराध आदि के मामलों में वर्षों से जेल में पड़े लोगों के मानवाधिकार की चिंता किसी को नहीं होती लेकिन ऐसे बेहद संवेदनशील मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत छुड़ाने के लिए इतिहासकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार आदि सभी एक साथ आगे आ जाते हैं। इन संदिग्धों के पक्ष में उतरी फौज स्वयं बताती है कि यह बहुत बड़ी बात है जिसे ढकने के लिए बेहद तत्परता से लोग सक्रिय हो गए हैं। देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, संस्थाओं के सदस्यों आदि को राजनैतिक एवं वैचारिक असहमति तथा राजनीतिक षडयंत्र में अंतर समझना होगा। भीमा-कोरेगांव के हिंसक घटना के आयोजन का औचित्य स्वयं षडयंत्र का इशारा करती है। राजनैतिक लाभ के लिए असहमति के नए-नए मुद्दे गढ़ कर जातीय एवं सामाजिक टकराव पैदा करना असहमति नहीं हो सकती। 1भारतीय लोकतंत्र संक्रमणकाल में है क्योंकि 60 वर्षों तक शासन करने वाला दल अचानक से चली गई सत्ता को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। जबकि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति पर भरोसा रखना चाहिए कि फिर उन्हें सत्ता का मौका भविष्य में मिलेगा। अत: उन्हें रचनात्मक कार्य करना चाहिए न कि षडयंत्रवादी राजनीति, क्योंकि जातीय एवं सामाजिक विभाजन व घृणा की परिस्थिति राजनीतिक बदलाव के समान जल्दी नहीं बदला करती।
- लोकतंत्र में सरकार के तीन अंग हैं- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है एवं विधायिका, कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका के कार्यों का भी लोग परीक्षण करने लगे हैं। लोगों की आस्था, विश्वास एवं समर्थन ने भी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यापकता एवं स्वीकार्यता प्रदान की थी। अत: न्यायपालिका के सभी राजनैतिक मामलों के निर्णयों का लोग विश्लेषण करते रहते हैं। इसलिए सरकार और सभी संस्थाओं को लोकतंत्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करना चाहिए।

प्रबळद्ध नागरिकों को राजनीतिक और वैचारिक असहमति तथा राजनीतिक षड्यंत्र में फर्क को समझना होगा लोकतांत्रिक देश और आजाद मळल्क होने के नाते भारत में लोगों को वैचारिक असहमति का अधिकार भी है, लेकिन जब बात लोकतांत्रिक संस्था के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की हत्या का षड्यंत्र रचने की हो तो लोकतांत्रिक असहमति की परिधि को नए सिरे से तय करना होगा। यह सही है कि पळिलस के महज हिरासत में लेने से कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यह भी सही है कि बिना किसी पळख्ता सळ्राग के पळिलस ने हिरासत में नहीं लिया होगा

3. स्पोर्ट्स कोड

THE CORE IAS

उत्तराखंड सरकार द्वारा खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, खेलांे के नाम पर कुकरमुत्तों की तरह फैले खेल संघों पर भी लगाम कस सकेगी। इससे न केवल वर्षो से चुनिंदा पदाधिकारियों के चंगुल में कैद खेल संघ खुली हवा में सांस ले सकेंगे, बल्कि काबिज पदाधिकारियों को अब इनसे बाहर जाना ही होगा। दरअसल प्रदेश में अभी कई नामी खेल संघों पर वर्षो से कुछ पदाधिकारी ही काबिज चल रहे हैं। इन खेलों में कौन खिलाड़ी खेलेगा अथवा नहीं, यह इनकी मनमर्जी पर ही अभी तक तय होता रहा है। नतीजतन कई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। इसके अलावा प्रदेश में कई ऐसे खेल संघ भी हैं जो केवल नाममात्र के लिए ही बने हुए हैं। नियमानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त खेल संघ को हर जिले में अपनी शाखा खोलने के साथ ही यहां खेल गतिविधियों का भी संचालन करना होता है। इसके लिए इन्हें प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य गठन के बाद तकरीबन 30 से अधिक खेल संघ इस समय कागजों पर चल रहे हैं। इनके मुख्य कार्यालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर जिलों में हैं, लेकिन अन्य जिलों में इनकी कोई इकाई नहीं है। नियमानुसार खेल संघों की हर जिले में इकाई होनी चाहिए और उसे खेलों के विकास के लिए काम करना चाहिए। यहां तक कि फुटबॉल जैसे सबसे बड़े खेल के संघ की भी सभी जिलों में इकाइयां नहीं हैं। समझा जा सकता है कि केवल दिखावे के लिए ये संघ काम कर रहे हैं। बावजूद इसके ये संघ खेल विभाग से खेलों के विकास के नाम पर आर्थिक मदद लेने में कामयाब रहते हैं। इससे कहीं न कहीं प्रदेश में खेलों के विकास की नेक मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही है। अब सरकार द्वारा स्पोर्ट्स कोड में संघों के पंजीकरण, इनकी मान्यता, पदाधिकारियों का कार्यकाल और मान्यता समाप्त करने संबंधी मानक तय कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें खामियां नजर आ रही हैं, इनमें खेल संघों के कार्यकाल का उल्लेख न होना प्रमुख है।

THE CORE IAS
THECORE

THE CORE CLASS PROGRAMME 2019

. THE HINDU ANALYSIS EDITORIAL BASED PRE/MAINS DISCUSSION /GUIDANCE CLASS

. ANSWER WRITING CLASSES FOR 2019

(ANSWER WRITING IS PROCESS NOT PRODUCT)

. CSE 2019 PRELIMS/ MAINS TEST SERIES

©TheCoreIAS
OFFICE:- CHAMBER 3 SECOND FLOOR BATRA CINEMA COMPLEX DR. MUKHERJEE NAGAR DELHI -09
CONTACT +91-8800141518/9540297983